माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर

(पुँवारका, सहारनपुर, उ0प्र0, पिन–247120)

Website- msuniversity.ac.in Email ID – registrar@msuniversity.ac.in

पत्रांक : 793 /07/प्रशा0/MSU/2025–26 दिनांक : 17-7-25

सेवा में,

01. प्राचार्य/प्राचार्या
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय

02. समन्वयक शैक्षणिक
विश्वविद्यालय परिसर

विषयः मा0 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग भारत सरकार द्वारा राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शिक्षा निदेशक, उ0शि0, डिग्री विकास अनुभाग, उ0प्र0, प्रयागराज के पत्र संख्या–डिग्री विकास/1140–41/2025–26, दिनांक 14.07.2025 एवं संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–3, उ0प्र0 शासन, लखनऊ के पत्र संख्या–1764/सत्तर–3–2025, दिनांक 10.07.2025 के साथ संलग्न अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण अनुभाग–3, उ0प्र0 शासन, लखनऊ के पत्र संख्या–204 भा0स0/23–3–2025–1764559, दिनांक 09.07.2025 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मा0 मंत्री सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार एवं राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक दिनांक 18 एवं 19 अगस्त, 2025 को आयोजित किया जाना है इस हेतु 03 बिन्दुओं पर सूचना उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गई है।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संलग्न पत्र में उल्लिखित दिशा–निर्देश के क्रम में संबंधित अपेक्षित एवं निर्धारित प्रारूप–ए एवं बी में सूचना भरकर तत्काल ई–मेल आई0डी0 dhedegreevikas@gmail.com पर उपलब्ध कराते हुये सूचना की एक कापी विश्वविद्यालय में भी प्रेषित कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक – यथोपरि।

भवदीय,
17-7-25
(कमल कृष्ण)
का0 कुलसचिव

प्रतिलिपि अधोलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

01. कुलपति कार्यालय को मा0 कुलपति महोदया के सूचनार्थ।
02. संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–3, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
03. अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण अनुभाग–3, उ0प्र0 शासन, लखनऊ
04. शिक्षा निदेशक, उ0शि0, डिग्री विकास अनुभाग, उ0प्र0, प्रयागराज

सहायक कुलसचिव

ई-मेल

प्रेषक,

शिक्षा निदेशक,(उ0शि0)
डिग्री विकास अनुभाग
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।

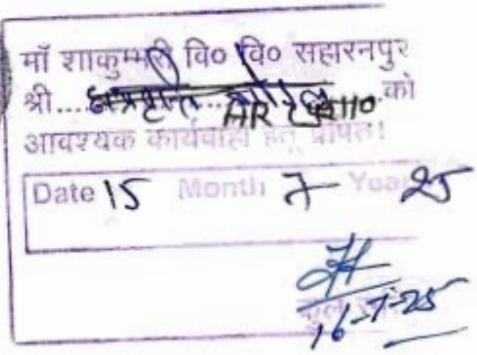

माँ शाकुम्भरी वि० वि० सहारनपुर
श्री... AR (Aca) ...को
आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
Date 15 Month 7 Year 25

सेवा में,

1- समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

2- कुलसचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश ।

पत्रांकः-डिग्री विकास / 1140 – 41 / 2025-26 दिनांक- 14 / 07 /2025

विषयः-मा0 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग भारत सरकार द्वारा राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया शासन के पत्र संख्या – 1764/सत्तर-3-2025 दिनांक- 10 जुलाई, 2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जो आपकों भी पृष्ठांकित है जिसके द्वारा मा0 मंत्री सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार एवं राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक दिनांक- 18 एवं 19 अगस्त 2025 को आयोजित किया जाना है इस हेतु 03 बिन्दुओं पर शासन द्वारा सूचना की अपेक्षा की गयी है ।

उक्त के क्रम में शासन का पत्र संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि आप अपने कार्यालय एवं क्षेत्रान्तर्गत आने वाले महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालय अपने से संबंधित अपेक्षित एवं निर्धारित प्रारुप –ए एवं बी में सूचना भरकर तत्काल इस कार्यालय के ई-मेल dhedegreevikas@gmail.com पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ।

संलग्नक-उक्तवत्

भवदीय,

Digitally signed by
AJIT KUMAR SINGH
Date: 14-07-2025
13:05:45

डॉ0(अजीत कुमार सिंह)
सहायक निदेशक,(उ0शि0)
कृते शिक्षा निदेशक,(उ0शि0)
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

पृष्ठांकन संख्या : डिग्री विकास/ / उसी तिथि को ।

प्रतिलिपि – संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग -03 उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित ।

डॉ0(अजीत कुमार सिंह)
सहायक निदेशक,(उ0शि0)
कृते शिक्षा निदेशक,(उ0शि0)
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

महत्वपूर्ण/समयबद्ध
संख्या-1764 /सत्तर-3-2025

प्रेषक,

प्रेम कुमार पाण्डेय,
संयुक्त सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उच्च शिक्षा, उ०प्र०,
प्रयागराज।

उच्च शिक्षा अनुभाग-3

लखनऊः दिनांक 10 जुलाई, 2025

विषयः मा० राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, भारत सरकार द्वारा राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग, उ०प्र० शासन के पत्र संख्या-204 भा०स०/26-3-2025-1764559, दिनांक 08.07.2025 (छायाप्रति संलग्न) का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से यह अवगत कराते हुए कि मा० मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन, पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० तथा भारत सरकार एवं राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक दिनांक 18 एवं 19 अगस्त 2025 को आयोजित किया जाना है। इस सम्बन्ध में दिनांक 18 एवं 19 अगस्त, 2025 को प्रस्तावित राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक के दृष्टिगत निम्नवत् कार्यवाही करने की अपेक्षा की गयी है:-

(1) अनुसूचित जातियों हेतु संचालित अपने विभाग से सम्बन्धित योजनाओं का प्रस्तुतिकरण (Presentation) तैयार करायें।

(2) मा० राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग द्वारा उपलब्ध कराये गये निर्धारित प्रोफार्मा (ए, बी, सी) पर अपने विभाग से सम्बन्धित सूचनाएं अंकित कर 03 कार्य दिवसों में उपलब्ध करायें।

(3) निदेशक, समाज कल्याण/जनजाति विकास एवं प्रबंध निदेशक, उ०प्र० अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, सम्बन्धित विभागों से समन्वय स्थापित करते हुए उक्त राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक हेतु आवश्यक प्रबंध करायें।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया प्रश्नगत प्रकरण में की गयी अपेक्षानुसार कार्यवाही करने एवं प्रकरण में चाही गयी सूचना संलग्न प्रारूप पर 02 कार्य दिवस में शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

Digitally signed by PREM KUMAR PANDEY
Date: 10-07-2025 17:03:46

(प्रेम कुमार पाण्डेय)
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि कुलसचिव, समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय, उ०प्र० को इस आशय से प्रेषित कि कृपया प्रश्नगत प्रकरण में समयान्तर्गत सूचना निदेशक, उच्च शिक्षा को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(प्रेम कुमार पाण्डेय)
संयुक्त सचिव।

महत्वपूर्ण/समयबद्ध
संख्या-1764 /सत्तर-3-2025

प्रेषक,

प्रेम कुमार पाण्डेय,
संयुक्त सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उच्च शिक्षा, उ०प्र०,
प्रयागराज।

उच्च शिक्षा अनुभाग-3 लखनऊः दिनांक 10 जुलाई, 2025

विषयः मा० राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, भारत सरकार द्वारा राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग, उ०प्र० शासन के पत्र संख्या-204 भा०स०/26-3-2025-1764559, दिनांक 08.07.2025 (छायाप्रति संलग्न) का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से यह अवगत कराते हुए कि मा० मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन, पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० तथा भारत सरकार एवं राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक दिनांक 18 एवं 19 अगस्त 2025 को आयोजित किया जाना है। इस सम्बन्ध में दिनांक 18 एवं 19 अगस्त, 2025 को प्रस्तावित राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक के दृष्टिगत निम्नवत् कार्यवाही करने की अपेक्षा की गयी है:-

(1) अनुसूचित जातियों हेतु संचालित अपने विभाग से सम्बन्धित योजनाओं का प्रस्तुतिकरण (Presentation) तैयार करायें।
(2) मा० राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग द्वारा उपलब्ध कराये गये निर्धारित प्रोफार्मा (ए, बी, सी) पर अपने विभाग से सम्बन्धित सूचनाएं अंकित कर 03 कार्य दिवसों में उपलब्ध करायें।
(3) निदेशक, समाज कल्याण/जनजाति विकास एवं प्रबंध निदेशक, उ०प्र० अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, सम्बन्धित विभागों से समन्वय स्थापित करते हुए उक्त राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक हेतु आवश्यक प्रबंध करायें।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया प्रश्नगत प्रकरण में की गयी अपेक्षानुसार कार्यवाही करने एवं प्रकरण में चाही गयी सूचना संलग्न प्रारूप पर 02 कार्य दिवस में शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(प्रेम कुमार पाण्डेय)
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि कुलसचिव, समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय, उ०प्र० को इस आशय से प्रेषित कि कृपया प्रश्नगत प्रकरण में समयान्तर्गत सूचना निदेशक, उच्च शिक्षा को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

Digitally signed by PREM KUMAR PANDEY
Date: 10-07-2025 17:04:25

(प्रेम कुमार पाण्डेय)
संयुक्त सचिव।

अति महत्वपूर्ण/समयबद्ध/
मा0 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग प्रकरण
संख्या-204 भा0स0/26-3-2025-1764559

प्रेषक,

एल0 वेंकटेश्वर लू,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव
गृह, बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, ग्राम्य विकास, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, नगर विकास, राजस्व, खाद्य एवं रसद, संस्थागत वित्त, पंचायती राज, कार्मिक, सार्वजनिक उद्यम, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग, उ0प्र0 शासन।

2- निदेशक,
समाज कल्याण विभाग/जनजाति विकास
विकास उ0प्र0 लखनऊ।

3- सचिव,
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग
लखनऊ, उ0प्र0।

4- राज्य मद्यनिषेध अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

5- निदेशक,
छत्रपति शाहू जी महाराज शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, भागीदारी भवन, गोमती नगर,
उ0प्र0 लखनऊ।

6- निदेशक, अनुसूचित जाति एवं जनजाति
शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान,
लखनऊ।

7- प्रबंध निदेशक,
यू0पी0 सिडको/उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, लि0
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 08 जुलाई, 2025

विषय - मा0 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, भारत सरकार द्वारा राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप निदेशक, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र संख्या-एन0सी0एस0सी0-सीसेल011/26/यू0पी0/2024-एडमिन, दिनांक 02-07-2025 (छायाप्रति संलग्न) का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से मा0 मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 तथा भारत सरकार एवं राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक दिनांक 18 एवं 19 अगस्त 2025 को आयोजित किये जाने की सूचना देते हुए निर्धारित प्रोफार्मा पर 10 दिनों के अन्दर सूचना उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

2- अवगत कराना है कि दिनांक 18 एवं 19 अगस्त 2025 को प्रस्तावित राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक में निम्नवत् योजनाओं/कार्यक्रमों पर विचार-विमर्श किया जाएगा:-

(क)- अनुसूचित जातियों के आर्थिक एवं सामाजिक कल्याण, केन्द्र प्रायोजित योजनाओं, केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं, आवास भूमि, रोजगार, छात्रवृत्ति एवं अन्य सम्बन्धित योजनाओं का अनुश्रवण।

(ख)- संविधान के तहत अनुसूचित जातियों को प्रदान की गयी सेवा सुरक्षा की निगरानी।

(ग)- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 (2015 एवं 2018 में संशोधित तथा उसके नियम) के अनुसार कार्यवाही के साथ ही मैनुअल स्कैवेंजिंग में लगे व्यक्तियों के पुनर्वास, अत्याचार से पीड़ितों को मुआवजे की स्थिति पर चर्चा की जाएगी।

(आर0पी0 चौधरी)
विशेष सचिव,
उच्च शिक्षा विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन

(गिरिजेश कुमार त्यागी)
विशेष सचिव,
उच्च शिक्षा विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

3- मा0 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग द्वारा निम्नवत् सूचनाएं 10 दिनों के अन्दर ई-मेल आई0डी0- dirhq-ncsc@gov.in और ccell-ncsc@nic.in पर निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं:-

(क)-एस0सी0/एस0टी0 एक्ट 1989 के सेक्शन-4 एवं 5 से सम्बन्धित सूचना (एनेक्जर-A)
(ख)-अनुसूचित जाति के कर्मचारियों के विरूद्ध लम्बित सतर्कता जाँच की स्थिति (एनेक्जर-B)
(ग)- अनुसूचित जनजातियों हेतु योजनाओं की सूचना (एजेक्जर-C)

4- अतः इस सम्बन्ध में अनुरोध है कि दिनांक 18 एवं 19 अगस्त 2025 को प्रस्तावित राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक के दृष्टिगत निम्नवत् कार्यवाही कराने का कष्ट करें:-

(1)-अनुसूचित जातियों हेतु संचालित अपने विभाग से सम्बन्धित योजनाओं का प्रस्तुतिकरण (Presentation) तैयार करायें।
(2)- मा0 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग द्वारा उपलब्ध कराये गये निर्धारित प्रोफार्मा (ए, बी, सी) पर अपने विभाग से सम्बन्धित सूचनाएं अंकित कर 03 कार्य दिवसों में उपलब्ध करायें।
(3)- निदेशक, समाज कल्याण/जनजाति विकास एवं प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, सम्बन्धित विभागों से समन्वय स्थापित करते हुए उक्त राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक हेतु आवश्यक प्रबंध करायें।

संलग्नक-यथोक्त।

Digitally signed by
LAKKU VENKATESHWARLU
Date: 08-07-2025
16:27:52
(एल0 वेंकटेश्वर लू)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-
1- पुलिस महानिदेशक, लखनऊ, उ0प्र0।
2- प्रमुख स्टॉफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3- उप निदेशक, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली को उनके पत्र दिनांक 02-07-2025 के क्रम में।
4- श्री जे0 राम, उप निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ, नोडल अधिकारी (मो0-8317041731) को इस आशय से प्रेषित कि समयान्तर्गत विभिन्न विभागों द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूचना के आधार पर समेकित सूचना दिनांक 14-07-2025 तक शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(रजनी कान्त पाण्डेय)
उप सचिव।

Government of India

National Commission for Scheduled Castes

(A Constitutional body set up under Article 338 of the Constitution of India)

File No. NCSC-CCell011/26/UP/2024-Admin

5th Floor, Lok Nayak Bhawan
Khan Market, New Delhi-110003
Date: 02.07.2025

To.

The Chief Secretary,
Govt. of Uttar Pradesh,
Secretariat, Lucknow-226001
Email: csup@nic.in

The Director General of Police,
Uttar Pradesh Police Headquarters,
1, Tilak Marg, Lucknow-226001
Email: dgp@up.nic.in

State Level Review Meeting to be taken by the National Commission for Scheduled Castes, Govt. with Govt. of Uttar Pradesh.

Sir,

I am directed to refer to your letter dated 26/11/2024 vide which the information for the State Level Review Meeting was received from the Govt. of Uttar Pradesh.

2. Now, the Commission has decided to conduct the SLRM of the Govt. of Uttar Pradesh on 18th and 19th August, 2025 with the Hon'ble Minister of Social Justice & Empowerment, Chief Secretary, Director General of Police & other Senior officers of the Govt. of Uttar Pradesh as per the programme mentioned below:

<u>18th and 19th August, 2025: -</u>

a. Monitoring of the progress of Schemes for Economic & Social Welfare of Scheduled Castes, Centrally Sponsored Schemes, Central Sector Schemes, housing land, employment, scholarships, other related schemes etc.
b. Monitoring of service safeguards provided to the Scheduled Castes under the Constitution.
c. Meeting to review action taken to control atrocities and progress in cases of atrocities as well as action as per SC/ST (POA) Act, 1989 (as amended in 2015 & 2018 and Rules thereof) as well as rehabilitation of persons engaged in manual scavenging, payment of compensation to victims of atrocities and other points as per SC/ST (PoA) Act, 1989 (as amended).

3. Further, the Commission has also sought information related to section 4 & 5 of SC/ST (PoA) Act, 1989 (Annexure-A), status of vigilance enquiry pending against SC employees (Annexure-B) & schemes for SCs (Annexure-C) in order to have more comprehensive and effective review of the SCs in the state of Uttar Pradesh. In this regard, it is requested that the requisite information in the Annexures A, B & C (copy enclosed) may also be provided along with aforesaid proformas within 10 days through email in soft copy at emails: dirhq-ncsc@gov.in & ccell-ncsc@nic.in. In addition, a department wise presentation on schemes and information, as per the proforma enclosed at Annexure-C may also be provided during the meeting.

4. You are requested to make all necessary arrangements to facilitate the **State Level Review** Meeting to be taken by the full Commission on 18th and 19th August, 2025.

This may please be treated as most immediate.

Yours faithfully

(Ayushi Rastogi)
Deputy Director

Encl: As above.

Copy to:

i. **Social Welfare,** Department, Govt. of Uttar Pradesh.
ii. **Director, NCSC,** State Office, Lucknow.

Annexure A

Additional information on Atrocities against SCs and related data

1. Cases pending for investigation for more than 6 months (District wise) (For the period 2020 to 2024)

S. No.	Date of Incident	Case Details PS/ FIR No. / Sections / Date of registration	Details of accused	Reasons for pending investigation	Remarks by Supervisory Authority

2. Cases registered/ Departmental enquiry u/s 4 of SC/ST (POA) Act, 1989 (as amended) (District wise) (For the period 2020 to 2024)

S. No.	Date of Incident	Case Details PS/ FIR No. / Sections / Date of registration	Name, Designation and details of accused officers	Status and outcome of the Case /Departmental enquiry	Present status of the Case/Departmental enquiry

3. Cases registered u/s 3 of SC/ST (POA) Act, 1989 (as amended) (District wise) (For the period 2020 to 2024)

S. No.	Date of Incident	Case Details PS/ FIR No. / Sections / Date of registration	Type of Atrocity (Sub-section & Clause of Section 3)	Description of the Incident	Action Taken (Police/Legal)	Present status of the case

4. As per Rule 13(1) of SC/ST (POA) Rules, 1995 (as amended), the State Government must ensure that administrative officers and staff appointed in atrocity-prone areas possess the right aptitude and understanding of the problems faced by Scheduled Castes and Scheduled Tribes. In this regard, provide following details:

S. No.	District	Atrocity-Prone Areas / Hot Spots	Colony visits, Lok Adalat by SP / Commissioner	Police patrolling / Counselling for victims etc.

5. Data on legal aid provided to Scheduled Castes (SCs) on a district-wise basis (from 2020 to 2024)

S. No.	District	Total Legal Aid Cases	Legal Aid Provided to SCs	Type of Legal Aid (e.g., Criminal, Civil, Family, etc.)	Total Expenses on Legal Aid	Govt. Funding Allocated

Annexure B

Vigilance Enquiry Pending Against Employees (General & SC Employees) (Department-wise)

To assess the status of vigilance enquiries pending against government employees, particularly Scheduled Caste (SC) employees, please provide detailed department-wise information on the number of cases under investigation. Provide the details in the following format:

Vigilance Enquiry Pending Against Employees (General & SC) (Department-wise)

S. No.	Department Name	Total Number of Employees Under Vigilance Enquiry	Total Number of SC Employees Under Vigilance	Nature of Allegation	Present Status of Enquiry	Interim Departmental Action Taken
						No. of Employees Suspended: No. of SC Employees Suspended. No. of Employees Transferred: No. of SC Employees Transferred:

Annexure C

Additional Information related to Economic and Social Development of SCs

1.	Name of State:			
	Total Geographical area:			
2.	Population:	Total (in Numbers)		
		SC (in Numbers)		
		SC in Percentage		
3	Birth Rate:	Overall		
		SC		
	Death Rate:	Overall		
		SC		
	Annual Population Growth:	Overall		
		SC		
	Life Expectancy:	Overall		
		SC		
4.	Density of Population:			
	Number of districts with sizable SC population (more than 20 %):			
	Number of identified backward SC settlements:			
	Name of Aspirational Districts & SC population:			
5.	Sex ratio:	Overall		
		SC		
6	State GDP (Per Annum in INR)			
	Sector wise Share in GDP (in %)	*Agriculture Sector*		
		Industry Sector		
		Service Sector		
	Per Capita Income (Per Annum in INR)	Overall		
		SC		
	Average Household Income (Per Annum in INR)	Rural	Overall	
			SC	
		Urban	Overall	
			SC	
7	% of population engaged in			
	Agriculture Sector:	Overall		
		SC		
	Industry Sector:	Overall		
		SC		
	Service Sector:	Overall		
		SC		
8.	Labour Force Participation Rate: LFPR is defined as the percentage of persons in labour	Labour Force Participation Rate of SC population		

	force (i.e. working or seeking or available for work) in the population. Male: Female: Overall:	Male: Female: Overall:		
9	**Unemployment Rate:** UR is defined as the percentage of persons unemployed among the persons in the labour force.	Overall	Male	
			Female	
			Average	
		SC	Male	
			Female	
			Average	
10	**Employment exchange** Number of persons currently registered in Employment exchange.	Overall	Male	
			Female	
			Average	
		SC	Male	
			Female	
			Average	
11	**BPL Families Data**	Total Families		
		SC Families		
	Rural Development			
12	*Deen Dayal Antyodaya Yojana - National Rural Livelihoods Mission (DAY-NRLM)* 1. Total number of SC households enrolled in DAY-NRLM. 2. Number of SHGs formed by SC members. 3. Amount and number of financial assistance packages provided to SC individuals or groups for setting up micro-enterprises and livelihood activities. 4. Number of SC beneficiaries who have received skill development training and secured gainful employment. 5. Number of SC women who have received support to become entrepreneurs. 6. Number of SC beneficiaries who availed interest subsidies for setting up enterprises. 7. Number and type of assets and infrastructure projects benefiting SC communities. 8. Number of SC beneficiaries who have gained access to banking and financial services. 9. Percentage of SC women participating in the scheme's initiatives. 10. Number of grievances filed by SC beneficiaries and their resolution status.			
13	*Deen Dayal Upadhyaya Grameen Kaushalya Yojana (DDU-GKY) is a skill training and placement program initiated by the Ministry of Rural Development, Government of India.* 1. Number of SC individuals have been enrolled in the DDU-GKY program. 2. Number of SC beneficiaries have successfully completed the skill training programs. 3. Number of SC beneficiaries have been successfully placed in jobs after completing their training. 4. What percentage of the overall beneficiaries are from the SC category?			

14	Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin (PMAY-G) 1. Number of SC individuals have been identified as beneficiaries under PMAY-G 2. Number of housing units have been constructed for SC beneficiaries under PMAY-G. 3. Number of SC beneficiaries have availed the interest subsidy under the Credit Linked Subsidy Scheme (CLSS) under PMAY-G. 4.Number of houses have been registered in the name of SC women or jointly with SC women.
	Urban Development
15	*Deen Dayal Antyodaya Yojana - National Urban Livelihoods Mission (DAY-NULM)* 1. Total number of SC households enrolled in DAY-NULM. 2. Number of SC beneficiaries who have received skill development training. 3. Number of SC beneficiaries who secured wage employment or self-employment after training. 4. Number of SHGs formed by SC members. 5. Amount and number of loans disbursed to SC individuals or groups for setting up micro-enterprises. 6. Number of SC beneficiaries who availed interest subsidies for setting up enterprises. 7. Number of SC beneficiaries using shelters provided for the urban homeless. 8. Number of SC street vendors who received support, such as access to institutional credit and social security. 9. Percentage of SC women participating in the scheme's initiatives. 10. Number of grievances filed by SC beneficiaries and their resolution status.
16	Pradhan Mantri Awas Yojana Urban (PMAY-U) 1. Number of SC individuals have been identified as beneficiaries under PMAY-U 2. Number of housing units have been constructed for SC beneficiaries under PMAY-U. 3. Number of SC beneficiaries have availed the interest subsidy under the Credit Linked Subsidy Scheme (CLSS) under PMAY-U. 4.Number of houses have been registered in the name of SC women or jointly with SC women.
	Agriculture and Farmer Welfare
17	Kisan Credit Card (KCC) Scheme: 1. Number of SC Farmers applied for KCC. 2. Number of KCCs Issued to SC Farmers.

	3. Total Loan Amount Disbursed in KCC 4. Percentage loan amount disbursed to SC farmers 5. Average Loan Amount per Farmer 6. Percentage of SC farmers given Interest Subsidies under KCC. 7. Number of SC Farmers Adopting Allied Activities (e.g., animal husbandry, fisheries):
18	PM Kisan Yojana 1. Number of SC Farmers are currently enrolled in the Scheme. 2. Any difficulty faced by SC farmers in producing land ownership documents to avail the scheme. 3. What alternative land ownership proofs are accepted under the scheme for SC farmers? 4. How many SC farmers receiving Direct Benefit Transfer (DBT) under the scheme? 5. Number of SC farmer's application rejected under the scheme and mention major reasons for rejection
	Health
19	Janani Suraksha Yojana (JSY) 1. Total number of SC women who availed of the benefits of JSY. 2. Number of institutional deliveries among SC women. 3. Total number of SC women who received financial assistance under JSY. 4. Total financial assistance provided to SC women under JSY. 5. Percentage of SC women who received prenatal and postpartum care under JSY.
20	Pradhan Mantri Surakshit Matritva Abhiyan (PMSMA) 1. Total number of SC women who availed of the benefits of PMSMA: 2. Number of institutional deliveries among SC women under PMSMA: 3. Total financial assistance provided to SC women under PMSMA: 4. Percentage of SC women who received prenatal and postpartum care under PMSMA: 5. Improvement in maternal and neonatal health indicators among SC population: o Number of maternal deaths reduced o Number of neonatal deaths reduced o Increase in average birth weight
21	Universal Immunization Programme (UIP) 1. Percentage of SC children under the age of 5 years have received vaccinations under UIP. 2. Are there sufficient vaccination facilities in SC-dominated areas, and are they easily accessible? 3. What measures have been taken to ensure that SC populations are aware of and have access to UIP services? 4. What are the main challenges and barriers faced by SC populations in accessing UIP services?

22	Rashtriya Bal Swasthya Karyakram (RBSK) 1. What percentage of SC children aged 0-18 years have undergone health screening under RBSK? 2. How frequently are health screenings conducted for SC children in schools and Anganwadi centres? 3. How many SC children have been diagnosed with defects at birth, diseases, deficiencies, or developmental delays under RBSK?
23	National Nutrition Mission 1. Number of Anganwadi Centers in SC-dominated areas. 2. Number of children (0-6 years), pregnant women, lactating mothers, and adolescent girls belonging to SC population enrolled under the scheme in the state. 3. How many SC-dominated districts and villages are covered in the State. 4. Are there any significant barriers to access faced by SC populations in benefiting from the scheme? 5. How frequently do SC children undergo health check-ups and growth monitoring at Anganwadi Centres?
24	Integrated Child Development Services (ICDS) 1. Number of SC children currently enrolled in ICDS. 2. Percentage share of SC children in total beneficiaries in ICDS. 3. Percentage of SC children, pregnant women, and lactating mothers have received supplementary nutrition through Anganwadi Centres. 4. How many Are Anganwadi Centers in SC-dominated areas adequately equipped with necessary infrastructure and resources like growth monitoring equipment, educational materials, and supplementary nutrition supplies? 5. What measurable outcomes related to the health and nutritional status of SC beneficiaries have been recorded in ICDS progress reports- Give details.
25	National Health Mission (NHM) 1. How many newly established or upgraded health facilities in established SC-dominated areas to improve healthcare access? 2. Mention state-specific action plans under the NHM addressed the unique healthcare needs of SC communities. 3. Number of Accredited Social Health Activists (ASHAs) under the NHM are from SC community and their percentage in total ASHA workers. 4. Percentage of NHM fund utilised for SC dominated area. 5. What percentage of Specific medical equipment and resources have been allocated to health centres in SC-populated regions under the NHM?
26	Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (PMJAY) /Ayushman Bharat 1. Number of newly established or upgraded health facilities under PMJAY in SC-dominated areas and its percentage in total new facilities in the state. 2. Percentage of funds allocated under PMJAY been specifically utilized to improve healthcare services for SC communities/areas. 3. Number of SC beneficiaries enrolled and receiving healthcare services under PMJAY. 4. Number of SC beneficiaries enrolled and receiving healthcare services secondary and tertiary care hospitalization under PMJAY. 5. Number of Rogi Kalyan Samitis (Patient Welfare Committees) catering to SC dominated areas under PMJAY.

	Social Welfare
27	**Midday Meal Scheme** 1. Number of SC students are currently enrolled in your school. 2. Number of SC students regularly receive midday meals at school. 3. What percentage of SC students in the state attend school more regularly since the introduction of the Midday Meal Programme? 4. How many SC students have had improved attendance due to the Midday Meal Programme? 5. Percentage of SC students in the State who have continued their education beyond primary school because of the midday meals.